श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश) मैडम एक आपत्ति है।

उपसभापति : क्या आपत्ति हो गई आपको ?

श्री संघ प्रिय गौतम : राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हमेशा हाउस में 12 घंटे चर्चा हुई है। तो इस बार चार घंटे की क्यों कटौती की जा रही है ? धन्यवाद प्रस्ताव पर 12 घंटे ही चर्चा होनी चाहिए। हमेशा 12 घंटे चर्चा हुई है।

उपसभापति : एक मिनट, आप अपना स्थाल ग्रहण करने की कोशिश करें तो मैं कुछ बोलूं। आप अपनी कोशिश में सफल हो गए इसलिए मैं आपको बताऊं कि यह बातें जो होती हैं जनरली आम तौर पर और खास तौर पर हाऊस में नहीं की जाती। इसके लिए इस हाउस ने एक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी नियुक्त की है। आप ही लोगों ने उसका गठन किया है। वह कमेटी बैठकर इसमें निर्णय लेती है। उस कमेटी ने कुछ हालात के तहत देखकर कोई निर्णय लिए है। इसलिए मैं आपके दुःख को समझ सकती हूं। मगर... **(व्यवधान)**

श्री संघ प्रिय गौतम : सभी कमेटियों का निर्णय सदन में प्रस्तुत होता है और सदन कमेटी से बड़ा होता है। इसलिए हमारे दुःख को दूर करने की कृपा करें।

उपसभापति : कुछ परम्पराएं होती हैं। कु आपत्तियां ऐसी होती हैं। सदन तो सबसे सुप्रीम है। मगर कुछ परम्पराएं होती हैं। उन परम्पराओं का और उन बातों का पालन करना यह भी हमारी एक जिम्मेदारी है। आज भी सुबह चेयरमैन साहब के सामने इसके ऊपर काफी विचार-विमर्श हुआ और यह निर्णय हुआ कि इस बात को कृपया यहां न उठाएं। जो कुछ हो सकता था वह हुआ है।... **(व्यवधान)** आप बोलिएगा बोलने को कौन मना करता है। 12 बजे रात तक बैठिएगा। तो 8 घंटे के 12 घंटे हो जाएंगे।

RE: CUT IN PLAN ALLOCATION TO DELHI GOVERNMENT

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली) उपसभाध्यक्ष महोदया, गवर्नमेंट आफ दिल्ली का जो प्लान एलोकेशन था, उस प्लान एलोकेशन में से 184 करोड़ रुपए सेंटर ने काट दिए हैं। 184 करोड़ रुपए काटने का जो फैसला उन्होंने किया है वह बदरपुर ताप बिजली घर को जो डेसू की देनदारियां थी, उसके एवज में वह रुपया बदरपुर ताप बिजली घर को दे दिया है। उपसभाध्यक्ष महोदया, इस प्लान की राशि को नान प्लान के अंदर कंवर्ट कर दिया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना स्टैंड हमेशा रहा है कि इन्होंने सभी स्टेट्स को लिखा कि कोई भी प्लान एलोकेशन का पैसा नान प्लान में खर्च नहीं किया जाए। परन्तु दिल्ली के अंदर, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट है, अपनी जो असिस्टेंस के पैसे थे, उन सब रुपए को 184 करोड रुपए को काट करके नान प्लान के अंदर डायवर्ट कर दिया। सबसे गलत बात यह हुई है कि यह राशि 22 फरवरी को काटी गई। 22 फरवरी के समय पर दिल्ली का प्लान 1560 करोड़ रुपए का था। उसमें से यह राशि काटने के बाद आखिर में तथा कुछ और कटौतियां करके अब यह राशि केवल 1146 करोड़ रुपए रह गई। करीब 400 करोड़ रुपए इसमें से काटा गया। अब यह योजना 1146 करोड़ रुपए की है इसका 2 फरवरी को पता चलता है। तो दिल्ली की जितनी स्कीमें थी... **(व्यवधान)**

[उपसभापति (श्री सुरेश पचौरी) : पीठासीन हुए]

विपक्ष के नेता (श्री सिकन्दर बख्त) : सदर साहब, जो सवाल उठाया जा रहा है इस पर मिनिस्टर साहब नोट दें। उनको यहां मौजूद होना चाहिए। अगर पार्लियामेंट्री एफ्येर्स मिनिस्टर हों तो कन्वे करें होम मिनिस्ट्री को। क्योंकि... **(व्यवधान)**

شری سکندر بخت: صدر صاحب جو سوال اٹھایا جا رہا ہے۔ اس پر منسٹر صاحب نوٹ دیں۔ انکو یہاں موجود ہونا چاہیے اگر پارلیمنٹری افیئرس منسٹر ہوں تو سنو سے کریں ہوم منسٹر کو کیونکہ..."مداخلت"...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : दूसरे मंत्री भी बैठे हुए हैं । Mr. Minister, please take note of it.

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : यह जो कटौती की है वह बिल्कुल इल्लीगल है, इम्मोरल है अनकंस्टीट्यूशनल है । क्योंकि राजनीति के तौर पर दिल्ली सरकार को कटघरे में रखने के लिए और उनकी सारी स्कीमों को काटने का ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रवैया रहा है, मैं इसको कंडम करता हूं और ये फौरी तौर पर रुपया वापस होना चाहिए ।

श्री० संघप्रिय गौतम : उपसभाध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल सही बात है ।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : उपसभाध्यक्ष महोदय, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है और एक यूनियन टेरिटरी होते हुए भी इसका अपना कंसॉलिडेटेड फंड है। या तो दिल्ली को एक स्टेट के तौर पर ट्रीट किया जाता फॉर फाइनेंशियल मैटर्स जैसा कि पहले ऐश्योर किया गया, तो दिल्ली की राशि 2500 करोड़ रुपए की होती और अगर इसको यू०टी० रखना है तो यू०टी० में टोटल घाटा सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा करती है । तो जो 1560 करोड़ रुपए प्लान में रखे गए थे, उसको इसमें पूरा किया जाना चाहिए था ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इसको आप देखें कि 1990–91 में सेंट्रल असिस्टेंट थी 30.4 परसेंट । 1991–92 में थी 32.83 यानि करीब 33 परसेंट थी । 1994–95 में जब बी०जे०पी० की गवर्नमेंट यहां बनी तो उसको कम करके केवल 15 परसेंट कर दिया गया । पिछले सालों में जितना रुपया दिया जाता था, उससे इस में कटौती की गई । डेसू का 1100 करोड़ रुपए का घाटा 1989–90 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरा किया । 1993 तक वे लगातार डेफिसिट पूरा करते रहे और 94–95 में आकर सारा रुपया डाइवर्ट कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने और दिल्ली के प्लान में से उसको काटा ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, दिल्ली राजधानी है । दुनिया भर की राजधानियों का यह तरीका है कि सेंटर पर उनकी गवर्नमेंट ऐडिशनल खर्चा करती है क्योंकि दिल्ली में तो 2500 करोड़ रुपया जो यहां पर आना चाहिए था उसको काट कर 1143 करोड़ कर दिया गया । यह दिल्ली की जनता के साथ एक मज़ाक किया गया । 22 फरवरी को जब आप काटते हैं तो जितनी स्कीमें थीं, 100 परसेंट सब स्कीमें रद्द हो गई । आखिरी महीने में दो सौ करोड़ रुपए खर्चा होना था । वह दो सौ करोड़ जब कट गया तो कारपोरेशन, एन०डी०एम०सी०, दिल्ली गवर्नमेंट, हॉस्पिटल, सबकी सारी स्कीमें बंद हो गई और एक भी स्कीम काम नहीं कर रही है । प्राइम मिनिस्टर ने ऐश्योर किया है कि मैं यह रुपया वापस दिलाऊंगा । प्रणब मुखर्जी साहब ने प्लानिंग कमीशन के अंदर यह कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को, होम मिनिस्ट्री को या किसी मिनिस्ट्री को राइट नहीं है कि प्लान का पैसा काट दें या प्लान का पैसा नहीं भेजें, यह प्रणब मुखर्जी साहब ने कहा कि वह प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन हैं और वह जो रुपया है, बिना उनकी इजाज़त लिए हुए कोई उसे काट नहीं सकता, फिर भी काट दिया गया ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, सिर्फ इतनी बात नहीं है । करीब सौ से ज्यादा स्कीमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसों में पड़ी हुई हैं, उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है । उनको कहीं भी रिलीज़ नहीं किया जा रहा है । जब दिल्ली की एक स्टेट असेंबली

†[ ]Transliteraiton in Arabic Script.

बन गई और उस लेजिस्लेटिव असेंबली का अपना कंसॉलिडेटेड फंड हो गया तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एक-एक स्कीम को रोक कर क्यों बैठी हुई है ? हॉस्पिटल बन गए, स्टाफ का सैंक्शन नहीं आ रहा है एक साल से । पैसा दिल्ली गवर्नमेंट ने देना है अपने पास से और सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिर्फ अपनी मोहर उस पर लगानी है । करीब आठ हॉस्पिटल हैं जो अधूरे पड़े हुए हैं क्योंकि वहां पर सैंक्शन नहीं आई । दिल्ली को नौ जिलों में विभक्त करने की बात थी, वह सेंट्रल गवर्नमेंट ने रोक रखी है, यमुना वाटर एकॉर्ड था, वह सेंट्रल गवर्नमेंट ने रोक रखा है । दिल्ली के साथ जो इतना स्टेप मदर्ली ट्रीटमेंट किया जा रहा है, उसके बारे में मेरा यह कहना था कि आज यहां दिल्ली में एक बहुत बड़ा डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा है । दिल्ली के हजारों लोग उस डिमॉन्स्ट्रेशन में आ रहे हैं । दिल्ली किसी एक जगह की नहीं है पूरे हिंदुस्तान के लोग यहां आते हैं । यहां पार्लियामेंट है, यहां राज्य सभा है, यहां लोक सभा है, यहां एम्बेसीज हैं । दिल्ली के अंदर हर रोज दस लाख लोग आते हैं और काम के बाद चले जाते हैं । उन सबके लिए जो स्पेशल असिस्टेंस दिल्ली को मिलनी चाहिए थी वह स्पेशल असिस्टेंस न देकर दिल्ली का जो अपना पैसा था, उसको भी काटा जा रहा है । मैं यह कहना चाहता हूं कि इसे या तो यूनियन टेरिटरी के तौर पर ट्रीट करिए और पूरा घाटा दीजिए या इसे स्टेट के तौर पर, फाइनेंशियल पावर्स के लिए स्टेट के तौर पर ट्रीट करें तो 2500 करोड़ दें परन्तु बड़ी अजीब बात हो रही है कि कोई मिनिस्टर भी इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है और दिल्ली के साथ इतना स्टेप मदर्ली ट्रीटमेंट, पोलिटिकल वेंडेटा किया जा रहा है । जब यह बिल पेश किया था तो देखिए, होम मिनिस्टर साहब ने उस समय यह बात कही थी । उन्होंने इसके लिए कहा है कि —

Now only three subjects have been left with the President. Rest of the subjects have been given to the Government of Delhi and I am sure we can build up a convention on the basis of what there is in the Constitution or what there is in the Bill. So far as I am concerned, I feel that most of the things can be done, if a healthy convention is built up. कोई कनवैंशन नहीं बनायी । यह होम मिनिस्टर साहब की एश्योरेंस थी, जब यह बिल पास हो रहा था। उसको भी उन्होंने नहीं किया और जो यहां लॉ एंड ऑर्डर है, उसमें 280 करोड़, 283 करोड़ रुपया लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर खर्च होता है, परन्तु वह सैंट्रल गवर्नमेंट के पास है । जब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो चीज है, उसका एक पैसा भी दिल्ली के प्लान में नहीं आना चाहिए तो वह 283—88 करोड़ रुपया दिल्ली को मिलना चाहिए ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): Please conclude.

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : दिल्ली को 50 करोड़ रुपया प्रोविडेंट फंड का सैंट्रल गवर्नमेंट दे रही थी, उसको भी उन्होंने रोक लिया, यह कहकर कि दिल्ली का कोई पब्लिक अकाउंट्स नहीं है । मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि सैंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली के साथ स्टैप मदर्ली ट्रीटमेंट बंद करे, पॉलिटिकल वैन्डेटा बंद करे नहीं तो दिल्ली के लोग भी मजबूर कर सकते हैं । आज तो एजीटेशन हुई है परन्तु कुछ दिनों के बाद यह एजीटेशन ऐसा रूप धारण करेगी और दिल्ली के साथ कोई स्टैप मदर्ली ट्रीटमेंट हम टॉलरेट नहीं करेंगे ।

SHRI INDER KUMAR GUJRAL (Bihar): Sir, I rise to suport what the hon. Member, Mr. Vijay Kumar Malhotra has said. I say so because not only do I see a rationale in what he has said, but also because, as a resident of Delhi and having functioned in various civic forums of the city, I feel concerned at the deterioration of several things,

Only a few months ago we had seen the ghastly sight of plague coming up. We also see pollution problems arising everywhere. We see the housing problem. We see that everyday, problems are mounting. After a long time, we have an elected Government in Delhi. It is a different matter that my party does not feel happy with the election of the BJP. But that is a secondary issue. An elected Government is an elected Government. Once an elected Government has been put in office, then you should not try to sabotage its functioning by withdrawing its resources. It is not only a question of State autonomy, but also a question of what we can do for the city. We all criticise the Government and the civic bodies and rightly for not doing several things. But funds are being arbitrarily withdrawn and nobody is willing to say, why it was done. Now, past debts are being settled like this. Who was responsible for those debts? Which Government was responsible? If the Central Government did it, then, Central Government should be held responsible for this. They should not penalise those who were not a party, if I may say so, to the default. I, therefore, urge the Government to kindly listen to this and not treat it as a party issue. It should treat it as an issue of the city. Even the Government of India is seated in the city. Since the Government of India and the Parliament are here and we see the deteriorating circumstances of the environment, naturally, it needs to be investigated. If electricity, medical health, education and housing are not kept up, we need to do something. We were having some hope, when the last Plan was finalised and when the Chief Minister of Delhi made a statement. We felt that at least, some effort was being made to try and ameliorate the situation. Now, we are confronted with this situation. I strongly urge the Government and I raise my voice in support of what Mr. Vijay Kumar Malhotra has said. Thank you

SHRI JAGMOHAN (Nominated): Sir, I strongly support what Mr. Vijay Kumar Malhotra has said and what Mr. Inder Kumar Gujaral has said. At present, Delhi is having the worst of both the worlds—worst as a Union Territory and worst as a State. They are not treating it properly and fairly. Apart from what has been said by Mr. Vijay Kumar Malhotra, I would like to bring one basic fact to the notice of the House. Delhi has now become the fourth most polluted city in the world and that has been created by the policies over which local Governments have no control. If the environment becomes bad, all of us are going to become sick. If a step-motherly treatment is accorded to Delhi, all of us are going to suffer in one way or the other. The whole nations productivity is going to suffer. Another important point which is usually forgotten by the critics of Delhi is this. They say, "Delhi is being given a liberal treatment as compared to the other cities." In fact, it is the other way round. Delhi's revenues are being eaten away. How? For example, technically speaking, lands are held in the name of the President because Delhi is technically a Union Teritory. Now, what happens when you convert the lands for commercial or for more intensive use as it happened in the Connaught Circus Extension or the other areas of New Delhi? In such a case, all the services have to be provided by the local bodies. Provision of additional water, additional electricity, additional sewerage, additional roadways, etc. are not covered under the Plan allocation. This being one position, another position is that the conversion charges are taken by the Government of India. And the value of the land, which runs into crores of rupees for a single plot, is all

taken by them. Nobody takes notice of that. I have repeatedly urged at the level of the Lt. Governor that this money should be given to the State of Delhi because the money is re-invested in that State. But nobody listens. Therefore, the issue is, apart from what the other Members have said, it should also be considered whether the money which is obtained out of conversion charges, ground rents and leases should be given by the Central Government back to the Union Territory so that it is utilised for the people of Delhi. Already, the population of Delhi has gone up to 110 lakhs. What are we going to do if the situation goes on like this?

Thank you very much, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): Mr. Gopalsamy. Not present. Mr. Nilotpal Basu... (*Interruptions*)

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : उसका क्या हुआ जो मैंने उठाया था दिल्ली के प्लान के बारे में ? 8—9 दिन रह गये हैं इन 8—9 दिनों में क्या होगा ? प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर एश्योर कर चुके हैं।

Some Minister should come forward and respond... (*Interruptions*)

उसका हुआ क्या ? (व्यवधान)...

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : मुझे लगता है ब्यूरोक्रेसी कर रहे हैं। व्यवधान) सरकार को एश्योरेंस देना चाहिए।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : दिल्ली के चीफ मिनिस्टर से कह दिया, प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया ,प्रणब मुखर्जी ने कह दिया। (व्यवधान) यह कहा से आयेगा ?

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : आपकी फीलिंग कन्वे कर देंगे। (व्यवधान)

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: Sir, let some Minister respond.

इस बारे में कोई डिसिजन होना चाहिए। (व्यवधान) यहां मिनिस्टर बैठे हुए हैं उनकी तरफ से कोई जवाब आना चाहिए। (व्यवधान)।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRIMATI MARGARET ALVA): Sir, the Home Minister is not here. We can convey their sentiments to the Home Minister... (*Interruptions*)...

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : सेंटीमेंट कन्वे करने की बात नहीं है। गवर्नमेंट की कई मीटिंग हो चुकी हैं... (व्यवधान)

श्री चतुरानन मिश्र (बिहार) : मैं अपने को एसोशिएट करता हूं। दिल्ली का मामला है इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

RE: DISHONOURING OF THE WEST BENGAL STATE LEGISLATURE BY THE DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

SHRI NILOTPAL BASU (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, the issue which I would like to raise is a very important one.

In fact, with a heavy heart, I am raising this issue. The issue pertains to the federal character of this country and to the very blatant violation by the Government of the principles of federal functioning. Sir, as you know, for a better functioning of the Department of Telecommunications, Telephone Advisory Committees have been formed by the Department of Telecommunica- t ions. Government of India, Now, in the constitution of these Committees, there is a component of nomination of elected MLAs of the